given provisional accreditation for conducting specified level of computer courses—'O' (Foundation), 'A' (Advanced Diploma), 'B' (Graduate) 'C' (Post-Graduate). The scheme is implemented through two professional bodies—Computer Society of India (CSI) and Institution of Electronics & Telecommunication Engineers (IETE). These professional bodies conduct examinations for various level of courses and the successful candidates are awarded appropriate certificates/diplomas. The institutions accredited for specific Computer Courses under the Scheme charge justifiable fees based upon infrastructure etc.

Setting up of Software Development Board

955. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a World Bank report has suggested the setting up of Software Development Board to give Indian Software Export a definite thrust ;

(b) if so, whether government have taken a decision to set up the board ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (c) The Government has accepted, in principle, to launch a Software Promotion Programme along the lines of recommendations in the World Bank founded report in order to give Indian Software Exports a definite thrust. The modalities of implementation and monitoring of the Programme are being worked out.

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम

956. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना को अभी आरम्भ किया जाना है तथा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रक्रियात्मक आधार पर इसे रोका गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने तथा अपेक्षित उद्देश्य-सिद्धि हेतु इसे कार्यान्वित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात तथा देश में उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) जी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। ईएचटीपी योजना को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 14 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या 42 (एन. डी)/92-97 के जरिए अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात् उद्योग मंत्रालय ने उद्योग (विकास तथा विनियम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत इस योजना के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 1993 तथा 2 मार्च, 1993 को गजट अधिसूचना सं. एस ओ/117(ई) जारी की।